

## न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 3/2020/अपील/एल०आर०एक्ट/कोटा

दायरा दिनांक 7.1.2020

किस्म अपील: धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

### उनवान

1. नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी बडगांव उर्फ नान्दना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. नन्दकिशोर पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी बडगांव उर्फ नान्दना तहसील लाडपुरा जिला कोटा  
..... अपीलार्थी

### बनाम

1. नगर विकास न्यास, जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

.....रेस्पोंडेंट

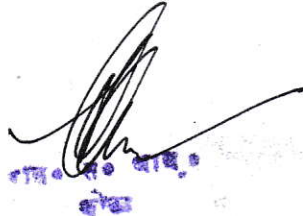
उपस्थित : श्री हेमन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी  
श्री शम्भूदयाल विजय अभिभाषक रेस्पोंडेंट-1

:: निर्णय ::

दिनांक 28.10.2021

अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.० राजस्व-11/2016/1310 दिनांक 18.5.2016 के विरुद्ध प्रथम अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश क्रमांक प.० राजस्व-11/2016/1310 दिनांक 18.5.2016 से विवादित आराजी ग्राम देवनगर उर्फ बोरतलाई पटवार हल्का गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा खसरा नम्बर 160/48 की 1.50 है० एवं ख० नं० 161/49 की 1.57 है० कुल किता 2 की 3.07 है० नहरी (सिवायचक) भूमि को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 के अनुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 (ए) के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को स्थानान्तरित करने से व्यथित होकर अपीलार्थीगया द्वारा राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील इस आशय की पेश की गई कि विवादित आराजी सिवायचक कृषि योग्य भूमि नहरी होने के बावजूद आबादी विस्तार हेतु रेस्पोंडेंट नं० 1 के नाम स्थानान्तरण कानून के विपरीत की है। अपीलांत वर्ष 2012 से ही उक्त कृषि योग्य आराजी को नीलामी पर रेस्पोंडेंट नं० 2 से प्राप्त कर काशत करते चले आ रहे है नीलामी बोली मे जमा की गई राशि की रसीद रेस्पोंडेंट नं० 2 द्वारा बाद मे ही दी जाती रही है। वर्ष 2016 मे भी उक्त कृषि भूमि को नीलामी के मार्फत मुनाफा काशत पर जुपाने हेतु चौथाई राशि जमा करवाकर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी रसीद अपीलांत को नही दी गयी है और अपीलांत नं० 1 को महेश पुत्र मोहनलाल के नाम से संबोधित करते हुये नोटिस दिनांकित 22.6.2016 प्रेषित कर रेस्पोंडेंट नं० 2 बोली निरस्त करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। अपीलांत क्रम 1 ने फसल बो गरडा बो रखी है जिस पर अपीलांत नं० 1 का कब्जा चला आ रहा है रेस्पोंडेंट नं० 2 को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। उक्त आराजी अपीलांत के पिता के खाते की थी और सीलिंग मे अधिग्रहण करने के पश्चात उक्त आराजी सीलिंग सिवायचक दर्ज हुई है और कृषि योग्य है। नीलामी का आदेश पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। सीलिंग सिवायचक कृषि योग्य भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति मे आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक

  
राज. भू. राजस्व. अधिनियम 1956  
कोटा

18.5.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलांत नं० 1 के पक्ष में नीलामी बहाल रखी जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गयी।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया जाकर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 अपीलांत के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांत का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि की नीलामी अपीलांत के नाम छोड़ी गई थी। बाद में रेस्पो० ने नीलामी खारिज दी जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बहस में यह भी बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांत के पिता के खाते की थी जो सीलिंग में अधिग्रहण करने के पश्चात सीलिंग सिवायचक दर्ज हुई है जो कृषि योग्य भूमि है। अतः आलौच्य आदेश पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांत स्वीकार करने का अनुरोध किया।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम-1 श्री शंभूदयाल विजय ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक थी। सिवायचक भूमि के संबंध में अपीलांत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अगर किसी प्रकार से अपीलांत हितबद्ध थे तो इनको सक्षम न्यायालय में रेगूलर वाद प्रस्तुत कर अपने हक हकूको को तय कराना था। अपीलांत द्वारा विवादित आराजी के कब्जे के संबंध में घोषणा का वाद पेश नहीं किया है तथा ना ही पत्रावली में ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध है। अतः अपीलांत विधिक तौर पर कोई अनुतोष प्राप्त करने वैधानिक अधिकारी नहीं है। अपील खारिज की जावे।
- 5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर कोटा द्वारा आलौच्य आदेश क्रमांक प.0 राजस्व-III/2016/1310 दिनांक 18.5.2016 से विवादित आराजी ग्राम देवनगर उर्फ बोरतलाई पटवार हल्का गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा खसरा नम्बर 160/48 की 1.50 है० एवं ख० नं० 161/49 की 1.57 है० कुल किता 2 की 3.07 है० नहरी (सिवायचक) भूमि को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 के अनुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 (ए) के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को स्थानान्तरित की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है उक्त भूमि नीलामी में उसके नाम छोड़ी गई थी बाद में नीलामी खारिज की गई जिसका रेस्पो० को कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम-1 का कथन है कि विवादित आराजी सिवायचक थी ऐसी स्थिति में अपीलांत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी प्रकार से हितबद्ध है तो सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर हक हकूक तय कराना चाहिये। विधिक तौर पर अपीलांत कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज योग्य है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से एवं अभिभाषक उभय पक्षकार के उपरोक्त तर्क पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादग्रस्त आराजी नहरी (सिवायचक) है जिसके संबंध में अपीलार्थी को कानूनी तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हम विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम-1 के इस मत से सहमत हैं कि यदि अपीलार्थी के वादग्रस्त आराजी के संदर्भ में किसी प्रकार हितबद्ध है तो उसको सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर हक हकूको को तय कराया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में अपीलार्थी द्वारा घोषणा का वाद पेश नहीं किया है तथा ना ही पत्रावली में ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। अतः उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश को न्यायोचित पाते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांत सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।
- 6 निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुसंग संभव)  
अति० संभागीय आयुक्त  
कोटा